



2026:AHC: 179988

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1025 वर्ष 2025

सरला देवी

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता	: कृष्ण मणि, विनय कुमार द्विवेदी, विनोद कुमार ओझा
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण मणि और राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 5, प्रयागराज द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के अंतर्गत एक आवेदन (सरला देवी बनाम मनोज केसरवानी), पुलिस थाना कौंधियारा, जिला प्रयागराज पर पारित आदेश दिनांक 31.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा बीएनएसएस, 2023 की धारा 175(3) के अंतर्गत पुनरीक्षणवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, जिसमें एक एफआईआर दर्ज करने और अन्वेषण के लिए निर्देश की मांग की गई थी, को खारिज कर दिया गया है।

बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत आवेदन में निर्धारित अभियोजन का वृत्तांत यह है कि विपक्षियों ने पुनरीक्षणवादी के पति से भूमि का एक टुकड़ा खरीदा था और उसके पश्चात उस पर निर्माण शुरू कर दिया था। यह आरोप है कि विपक्षियों ने उनके द्वारा वास्तव में खरीदी गई भूमि

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



से आगे निर्माण का विस्तार करना शुरू कर दिया और, पुनरीक्षणवादी के पति द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद, बलपूर्वक निर्माण जारी रखा।

परिणामस्वरूप, 13.10.2024 को, पुनरीक्षणवादी के पति ने निर्माण को रोकने के अनुरोध के साथ '112' डायल करके पुलिस को बुलाया।

यह आरोप है कि विपक्षियों की ओर से कई व्यक्ति मौके पर एकत्र हो गए और कहासुनी हुई। पुनरीक्षणवादी के अनुसार, उसके पति, हरि मोहन साहू पर विपक्षियों द्वारा हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनके पैर में चोट सहित अन्य चोटें आईं। यह आगे अभिकथन है कि उसके पुत्रों, फूल कुमार और किशन कुमार पर भी हमला किया गया और उनके हाथों में अस्थिभंग सहित गंभीर चोटें आईं।

यह आगे अभिकथन है कि उसी घटना के दौरान, विपक्षियों में से एक का पुत्र अनिल केसरवानी फिसल कर सड़क पर गिर गया और उसके सिर में चोटें आईं, जिसके कारण तत्पश्चात उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना के आधार पर, पुनरीक्षणवादी के पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध एक आपराधिक वाद दर्ज किया गया, और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुनरीक्षणवादी की शिकायत यह है कि, उसके पति और पुत्रों पर कथित हमले के बावजूद, उसके कहने पर कोई प्रति-वाद दर्ज नहीं किया गया।

विद्वान मजिस्ट्रेट ने, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के उपरांत, आवेदन को खारिज कर दिया। यह दर्ज किया गया है कि, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, पुनरीक्षणवादी के पति और उसकी ओर से व्यक्तियों ने स्वयं विपक्षियों पर हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप अनिल केसरवानी को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। यह आगे ध्यान दिया गया है कि हरि मोहन और अन्य के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं 186, 149, 115, 352, 251 और 351(2) के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 186 वर्ष 2024 दर्ज किया गया था और अन्वेषण के दौरान, तत्पश्चात बीएनएस की धाराएं 190, 191(3) और 109 जोड़ी गईं।

कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और शेष व्यक्तियों के संबंध में विवेचना जारी होना बताया गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान मजिस्ट्रेट ने आगे दर्ज किया कि, इस आरोप के समर्थन में कि पुनरीक्षणवादी के पति और पुत्रों पर हमला किया गया था, कोई चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई थी और जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री से कथित घटना में उन्हें चोटें आने का कोई प्रथम दृष्टया मामला प्रकट नहीं होता है।

पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने हरि मोहन साहू से संबंधित चिकित्सा दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर भरोसा करते हुए पूर्वोक्त निष्कर्षों पर प्रहार किया है, जो संकेत देते हैं कि उनका 15.10.2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण किया गया था। उक्त दस्तावेजों में दर्द की शिकायत के साथ, दाहिने घुटने और दाहिनी जांघ के निचले हिस्से पर 14 सेमी × 8 सेमी आकार की कोमलता के साथ सूजन दर्ज की गई है, और एक्स-रे की सलाह दी गई थी।

दिनांक 16.10.2024 की एक्स-रे रिपोर्ट की एक फोटोकॉपी भी अभिलेख पर रखी गई है, जिसमें दाहिने घुटने और जांघ का परीक्षण किया गया था और दाहिने घुटने के संबंध में दर्ज निष्कर्ष था: "घुटने में धात्विक प्रत्यारोपण के साथ पुराना ऑपरेशन"।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वोक्त चिकित्सा सामग्री यह प्रदर्शित करती है कि हरि मोहन को घटना में चोटें आई थीं और, इसलिए, विद्वान मजिस्ट्रेट को बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत आवेदन को खारिज नहीं करना चाहिए था।

प्रस्तुत किए गए अभिवेदनों पर विचार करने और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात, यह महत्वपूर्ण है कि दिनांक 13.10.2024 की घटना विवाद में नहीं है। अनिल केसरवानी की मृत्यु के संबंध में हरि मोहन और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध उसी घटना से उत्पन्न एक आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका था। पुनरीक्षणवादी मुख्य रूप से अपने पति, हरि मोहन से संबंधित दिनांक 15.10.2024 और 16.10.2024 के चिकित्सा दस्तावेजों पर भरोसा करना चाहती है। हालांकि, उक्त दस्तावेज यह स्थापित नहीं करते हैं कि उसमें उल्लिखित चोट दिनांक 13.10.2024 की घटना के दौरान कारित हुई थी। बल्कि, दिनांक 16.10.2024 की एक्स-रे रिपोर्ट दाहिने घुटने में धात्विक प्रत्यारोपण के साथ एक पुराने ऑपरेशन की स्थिति दर्ज करती है। इस प्रकार, रेडियोलॉजिकल निष्कर्ष इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं कि प्रश्नगत घटना में हरि मोहन के पैर में कोई नया अस्थिभंग हुआ था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, अभिलेख पर ऐसी कोई चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट या अन्य समकालीन चिकित्सा सामग्री नहीं है जो यह प्रदर्शित करती हो कि पुनरीक्षणवादी के पुत्रों, अर्थात्, फूल कुमार और किशन कुमार को इस घटना में कथित गंभीर चोटें आईं, जिसमें उनके हाथों में अस्थिभंग शामिल है। इसलिए, उनकी चोटों के संबंध में आरोप स्वतंत्र चिकित्सा सामग्री द्वारा असमर्थित रहता है।

बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत आवेदन पर विचार करने के चरण पर, मजिस्ट्रेट को न्यायालय के समक्ष रखे गए आरोपों और सामग्री पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि क्या परिस्थितियां एक एफआईआर दर्ज करने और अन्वेषण के लिए निर्देश की मांग करती हैं। इस प्रावधान का आशय केवल एक प्रति-वृत्तांत या प्रति-मामला स्थापित करने के प्रयोजन के लिए लागू किया जाना नहीं है, जहां न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पुलिस विवेचना की आवश्यकता वाले किसी प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है।

इस न्यायालय का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार सीमित है। जब तक कि आक्षेपित आदेश स्पष्ट अवैधता, तात्त्विक अनियमितता, विकृति, या न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफलता से ग्रस्त न हो, केवल इसलिए हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है क्योंकि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव हो सकता है।

मामले पर समग्र विचार करने पर, यह न्यायालय पाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार किया है और एक एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार करने के कारण निर्दिष्ट किए हैं। ऐसी कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि या विकृति प्रदर्शित नहीं की गई है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग कर सके।

परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण **खारिज** किया जाता है और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश एतद्वारा पुष्ट किया जाता है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां बीएनएसएस की धारा 175(3) के अंतर्गत आवेदन पर पारित आदेश की वैधता और शुद्धता तक ही सीमित हैं। इस निर्णय में अंतर्विष्ट किसी भी बात का अर्थ मुकदमा अपराध संख्या 186 वर्ष 2024 के गुण-दोष पर या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के दोष या बेगुनाही पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

विवेचना और उससे उत्पन्न होने वाली कोई भी अनुवर्ती कार्यवाहियां सख्ती से विधि के अनुसार आगे बढ़ेंगी।

18 अगस्त, 2026

प्रवेश मिश्रा

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”